International Journal of Education and Science Research Review
Volume-11, Issue-6 Nov-Dec-2024 E-ISSN 2348-6457
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Impact Factor - 7.02 Email- editor@ijesrr.org

भारत में क्षेत्रीय आर्थिक असमानता और सहचर पूंजीवादी : राज्यों के बीच विकास अंतर का विश्लेषण है

Mukesh Kumar

Research Scholar, MJP Rohilkhand University Bareilly

Dr. Manmohan Singh

Assistant Professor and HOD Dept. Of Political science JSH PG College Amroha.

सार

वर्तमान में असमानता ही देश में सबसे बड़ी समस्या है. हमें इसे ख़त्म करना होगा. सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता और औद्योगिक असमानता ही देश को विकसित बनाने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, सामाजिक असमानता के कारण ही आज समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता, इंसानियत और नैतिकता ख़त्म होता जा रहा है. व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज को जाति और धर्म में बांटा जा रहा है, आर्थिक असमानता के कारण ही आज समाज में अमीरों और अरबपतियों की संख्याँ तो बढ़ रही है, परन्तु समाज के गरीब लोग या तो जिस हाल में थे आज भी वही यथा स्थिति बनी हुई है। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय का नींव है. आर्थिक न्याय के बिना हम सामाजिक न्याय का कल्पना भी नहीं कर सकते. यदि वास्तव में हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो हमें आर्थिक न्याय को मजबूत बनाना ही होगा. निजीकरण-उदारीकरण-वैश्वीकरण के दौर में हर तरह की असमानता बढ़ी है। अमीरों-गरीबों के बीच, उद्योग-कृषि के बीच, शहर-देहात के बीच असमानता बढ़ी है। इसी तरह क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी है।इस अध्ययन में, हम भारत में क्षेत्रीय स्तर पर वित्तीय विकास में असमानताओं की जांच करते हैं। अध्ययन के प्रमुख शोध प्रश्न हैं: हम उप-राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय विकास के स्तर को कैसे मापते हैं? राज्यों में वित्तीय विकास कितना असमान है? क्या यह वित्तीय संस्थानों के स्वामित्व के अनुसार भिन्न होता है? इन शोध प्रश्नों का पता लगाने के लिए, हमारा अध्ययन 1996-2015 को कवर करने वाले 25 भारतीय राज्यों के लिए तीन अलग-अलग बैंक समूहों - सार्वजनिक, निजी और विदेशी के लिए उप-राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र बैंकिंग विकास सूचकांक विकसित करता है। हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि सुधारों के बावजूद, पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में अग्रणी उच्च आय और अधिक विकसित क्षेत्रों में बैंकिंग विकास काफी अधिक है। इसके अलावा, हम पाते हैं कि सार्वजनिक बैंकों सहित सभी बैंक समूह विकसित क्षेत्रों में अधिक केंद्रित हैं। कुल मिलाकर, पिछले कुछ वर्षों में समग्र बैंकिंग सूचकांक में शीर्ष तीन और निचले तीन राज्यों की स्थिति अपरिवर्तित रही है, जो क्षेत्रीय विकास की एकतरफाता को दर्शाता है। हम 2009-15 की अवधि के दौरान कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों की रैंकिंग में सुधार भी देखते हैं।

मुख्य बिन्दु: भारत में क्षेत्रीय आर्थिक असमानता, सहचर पूंजीवादी, राज्यों के विकास, विश्लेषण.

परिचय :-

यह आम जानकारी की बात है कि निजीकरण-उदारीकरण-वैश्वीकरण के दौर में हर तरह की असमानता बढ़ी है। अमीरों-गरीबों के बीच, उद्योग-कृषि के बीच, शहर-देहात के बीच असमानता बढ़ी है। इसी तरह क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी है।

बढ़ती क्षेत्रीय असमानता का एक आंकड़ा इस प्रकार है

1960-61 में दिल्ली का प्रति व्यक्ति उत्पाद 668 रुपये था जबकि बिहार का 215 रुपया। 1990-91 में यह आंकड़ा क्रमशः 11057 और 2660 रुपया हो गया। 2014-15 में यह फिर क्रमशः 252011 रुपया तथा 34850 रुपया हो गया। अनुपात के तौर पर देखें तो दिल्ली और बिहार के प्रति व्यक्ति उत्पाद में 1960-61 में अनुपात करीब तीन गुना तक था जो 1990-91 में करीब चार गुने का हो गया। पर उसके बाद के पच्चीस वर्षों में यह तेजी से बढ़कर करीब आठ गुने का हो गया। दिल्ली देश की राजधानी है जबकि बिहार देश का एक सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश। इनके बीच बढ़ती असमानता यह भी दिखाती है कि राजधानी और दूर-दराज के प्रदेश किस तरह से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि राजधानी में ज्यादा धनी लोगों तथा कंपनियों के मुख्यालयों के संकेन्द्रण की वजह से वहां प्रति व्यक्ति उत्पाद ज्यादा हो सकता है। पर यदि अन्य ज्यादा आगे बढ़े हुए प्रदेशों महाराष्ट्र से तुलना करें तो भी यह असमानता बढ़ती नजर आयेगी। हां, यह जरूर है कि स्वयं महाराष्ट्र के भीतर देश के सबसे गरीब इलाकों में से कुछ मिल जायेंगे मसलन विदर्भ का इलाका। ठीक उदारीकरण के दौर में इस क्षेत्रीय असमानता के बढ़ने के निश्चित कारण हैं। उदारीकरण की नीतियां लागू होने के साथ न केवल सरकारों ने उद्योग-धन्धों से अपने हाथ खींचे बल्कि प्रदेश सरकारों ने अपने-अपने यहां देशी-विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिता करनी शुरू की।

इसके लिए पूंजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा छूटें-रियायतें व प्रोत्साहन की घोषणाएं की गई। देशी-विदेशी पूंजी उधर की ओर ही आकर्षित हुई जहां यह सबसे ज्यादा था। अब सबसे ज्यादा छूटें वे ही प्रदेश दे सकते थे, जो पहले से बेहतर स्थिति में थे यानी आय ज्यादा थी जो पहले से ज्यादा औद्योगीकृत थे। इस तरह वह दुष्चक्र शुरू हुआ जो पहले से आगे बढ़े हुए प्रदेशों को और आगे ले गया। पीछे छूटते प्रदेश और पीछे छूटते चले गये।

पूंजी को आकर्षित करने की इस होड़ ने पूंजीपतियों को और ज्यादा लूट का मौका दिया है और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया है। अक्सर ही पूंजीपति इन रियायतों-प्रोत्साहनों का फायदा उठाकर नयी जगह फिर इसी तरह की रियायत-प्रोत्साहन का फायदा उठाने चल देते हैं।

इस प्रवृत्ति में मजदूर वर्ग की सौदेबाजी की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। फैक्टरी के स्थानांतरण के भय से मजदूर वैसे ही दबाव में रहते हैं ऊपर से प्रदेश सरकारें भी हर तरह से मजदूरों के संगठन और संघर्ष को बाधित करती हैं। ऐसा वे प्रदेश के औद्योगीकरण और पूंजीपतियों को पलायन करने से रोकने के नाम पर करती हैं।

मजदूर वर्ग की इस गिरती हालत के इतर स्वयं पूंजीपति वर्ग के भीतर भी इस बढ़ती असमानता ने आपसी रगड़ को जन्म दिया है। विभिन्न प्रदेशों के क्षेत्रीय पूंजीपति अपने प्रदेश के पिछड़ते जाने से असंतुष्ट हैं। वे अपने प्रदेश के लिए केन्द्र से ज्यादा सहायता की मांग करते हैं। ठीक इसके उलट आगे बढ़े हुए प्रदेशों के पूंजीपति दूसरे तरह की मांग करते हैं। इसी के नतीजे के तौर पर अभी तमिलनाडु की विधानसभा ने माल और सेवा कर विधेयक (जीएसटी बिल) को अनुमोदित नहीं किया।

एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति की बात करने वाले संघ परिवार के स्वयं सेवक जब दिल्ली में सत्तानशीन हुए तो उन्होंने सहकारी संघवाद (को-ओपरेटिव फेडरलिज्म) की बात की। जुमले उछालने में उस्ताद इन संघियों ने यह कभी स्पष्ट नहीं किया कि इस जुमले का क्या आशय है, और इसके तहत क्या किया जायेगा।

वैसे उदारीकरण की धुर समर्थक इस केन्द्रीयतावादी सरकार को इसकी चिन्ता भी नहीं है। चिन्ता तो उन्हें होनी चाहिए जो पिछड़ रहे हैं। पर पूंजीपति वर्ग का हिस्सा होने के चलते वे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा वे यही कर सकते हैं कि बेहतर सौदेबाजी के लिए कोई नया रास्ता ढूंढे। वैसे अब इन रास्तों की गुंजाइश भी बहुत कम रह गई है।

असमानता ही देश में सबसे बड़ी समस्या है

वर्तमान में असमानता ही देश में सबसे बड़ी समस्या है. हमें इसे ख़त्म करना होगा. सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता और औद्योगिक असमानता ही देश को विकसित बनाने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है.

सामाजिक असमानता के कारण ही आज समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता, इंसानियत और नैतिकता ख़त्म होता जा रहा है. व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज को जाति और धर्म में बाँटना जायज नहीं आर्थिक असमानता के कारण ही आज समाज में अमीरों और अरबपतियों की संख्याँ तो बढ़ रही है परन्तु समाज के गरीब लोग या तो जिस हाल में थे आज भी वही पे खड़े हैं या नहीं तो और गरीब ही होते जा रहे हैं. आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय का नींव है. आर्थिक न्याय के बिना हम सामाजिक न्याय का कल्पना भी नहीं कर सकते. यदि वास्तव में हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं तो हमें आर्थिक न्याय को मजबूत बनाना ही होगा.

शैक्षिक असमानता के कारण ही हम समाज में वंचित वर्गों को अच्छी शिक्षा दे पाने में असफल साबित हो रहे हैं. हम जानते हैं कि शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का विकास हो ही नहीं सकता. शिक्षा ऐसी हो जो हमें सोचना सिखाये, कर्त्तव्य और अधिकार का बोध कराये, हमें हमारा हक दिलाये और हमें समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाये. क्या हम ऐसी शिक्षा समाज के सभी वर्गों को दे पाने में सफल साबित हो रहे हैं?

क्षेत्रीय असमानता के कारण ही आज हम देश के सभी भागों खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने में विफल साबित हो रहे हैं. भारत को विकसित देशों के श्रेणी में लाने के लिए हमें सुदूरवर्ती गाँवों में विकास के किरणों को पहुँचाना होगा. आखिर हम दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के अनुपात में ही अन्य शहरों और गाँवों का विकास करने में असफल क्यों साबित हो रहे हैं? हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा. यदि हम इन्ही शहरों जैसे और शहर बनाने में कामयाब होते हैं तो न सिर्फ इन शहरों पर से लोगों का दवाब कम करने में कामयाब होंगे बल्कि हमें इस तरह के और कई अन्य शहर भी विकसित करने में सफलता मिलेगी जो क्षेत्रीय असफलता को ख़त्म करने में मील का पत्थर साबित होगा।

औद्योगिक असमानता के कारण ही आज हमें कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पर रहा है. ऐसा देखा जा रहा है कि जिस शहर में पहले से ही बहुत सारे उद्योग-धंधे लगे हुए हैं आज भी उन्ही जगहों पर नए-नए उद्योग और कल-

कारखाने लगते जा रहे हैं. हमें नए-नए औद्योगिक शहर बसाने की जरुरत है. इसके दो फायदे होंगे. एक तो पुराने औद्योगिक शहरों पर जो लोगों का बोझ बढ़ता जा रहा है वह कम होगा और दूसरा हम नए औद्योगिक शहर बसाने में भी कामयाब होंगे.

इसी तरह बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, रेल और कृषि आदि अनेक क्षेत्रों में असमानताओं से आम जनों को जूझना पर रहा है. कहीं चौबीसों घंटे बिजली तो कहीं आज भी लोग लालटेन और ढिबरी युग में जीने को विवश हैं. कहीं पानी ही पानी तो कहीं पानी के लिए हाहाकार. कहीं पक्की सड़कों की भरमार तो कहीं कच्ची सड़क भी नहीं. कहीं बड़े-बड़े अस्पताल तो कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं. कहीं रेलवे लाइनों की जाल तो कहीं रेलवे का घोर अभाव. कहीं किसानों के लिए आधुनिक संसाधनों की भरमार तो कहीं किसान बेहाल. यह असमानता उस घुन की तरह है जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला बनाता जा रहा है. हमें हर हाल में इस असमानता को मिटाना ही होगा ।

असमानता पर चर्चाओं का ध्यान व्यक्तियों के बीच बढ़ती वैश्विक आय और धन असमानता, देशों के बीच असमानता और एक देश के भीतर विभिन्न जनसंख्या समूहों के बीच असमानता पर केंद्रित रहा है। स्थानिक असमानता, यानी भौगोलिक क्षेत्रों में असमानता पर भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है, वित्तीय क्षेत्र में असमानता का कम पता लगाया गया है।

इस अध्ययन में, हम उप-राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय विकास की जांच करते हैं। हमारे प्रमुख शोध प्रश्न हैं: हम उप-राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय विकास के स्तर को कैसे मापते हैं? राज्यों में वित्तीय विकास कितना असमान है? क्या यह वित्तीय संस्थानों के स्वामित्व से भिन्न होता है? हम इनकी जांच एक बड़े देश भारत के संदर्भ में करते हैं। शोध प्रश्नों का पता लगाने के लिए, हमारा अध्ययन 1996-2015 को कवर करने वाले 25 भारतीय राज्यों के लिए तीन अलग-अलग बैंक समूहों - सार्वजनिक, निजी और विदेशी के लिए उप-राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग विकास सूचकांक विकसित करता है। यद्यपि कुछ राज्यों (केरल) का विकास स्तर कुछ हद तक विकसित देशों के समान है, लेकिन अन्य राज्यों का विकास स्तर काफी पीछे है। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से, क्षेत्रीय असमानताएँ काफी बढ़ गई हैं।

राज्यों में वित्तीय विकास के स्तर में असमानताएँ लगातार बनी हुई हैं। संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 1960 और 1970 के दशक में कई नीतियाँ, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र को लक्षित करके अपनाई गईं। इनमें 1969 और 1980 में सामाजिक नियंत्रण और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कम विकसित क्षेत्रों में निवेश, निर्देशित ऋण, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए 60% ऋण-जमा अनुपात पर जोर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना शामिल थी।

इसके अलावा, वित्तीय विकास व्यवसाय और निजी क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय फर्म वित्त के बाहरी स्रोतों पर काफी हद तक निर्भर हैं और इसलिए, बैंकों तक खराब पहुँच पिछड़े राज्यों में व्यवसाय विकास के लिए वित्त के स्रोतों को सीमित कर सकती है।

हमारा अध्ययन कई मामलों में मौजूदा साहित्य में योगदान देता है। सबसे पहले, हमारा अध्ययन उप-राष्ट्रीय स्तर पर है और क्रॉस-कंट्री/राष्ट्रीय स्तर के अध्ययनों की कुछ सीमाओं को पार करता है। एक बड़े विविध देश में, उप-राष्ट्रीय तस्वीर राष्ट्रीय स्तर से बहुत अलग हो सकती है। दूसरे, हम विभिन्न संकेतकों पर विविध सूचनाओं को सारांशित करते हुए अद्वितीय राज्य स्तरीय बैंकिंग विकास सूचकांक बनाते हैं। इससे भारतीय राज्यों में वित्तीय विकास की स्थिति का व्यापक

आकलन संभव हो जाता है। तीसरे, हम तीन बैंक समूहों (सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंक) पर अलग-अलग विचार करते हैं और बैंकों के विभिन्न स्वामित्व के प्रतिस्पर्धी प्रभावों को पकड़ते हैं।

हालांकि सभी बैंक वित्तीय विकास और गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में उनके योगदान के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विभिन्न बैंक समूहों में अंतर करना उपयोगी है क्योंकि भारतीय सार्वजनिक बैंक राष्ट्रीय नीति प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि निजी बैंकों को अपने स्वयं के बाजारों को आगे बढ़ाने की कुछ अधिक स्वतंत्रता होती है। इसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय बैंक मुख्य रूप से महानगरीय शहरों में स्थित हैं और हम यह जांचना चाहते थे कि उनका व्यवहार घरेलू बैंकों से अलग है या नहीं। फिर भी, इन अंतरों के बावजूद सभी बैंक समूहों (20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों सहित) को शुद्ध बैंक ऋण के 40% के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। हाल ही में, विशेष रूप से संकट (जैसे 2007-08 वैश्विक वित्तीय संकट) में वित्तीय स्थिरता में योगदान देने में सार्वजनिक बैंकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, हमारे अध्ययन में शामिल वर्ष 1991 के सुधारों के बाद से भारत के आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। साथ ही, हमारा सूचकांक वित्तीय गहराई (ऋण/जीडीपी अनुपात द्वारा कैप्चर किया गया) और आउटरीच संकेतक (प्रति बैंक शाखा कवर की गई जनसंख्या द्वारा प्रॉक्सी) दोनों को जोड़ता है। अंत में, हमारे अध्ययन के न केवल भारत के लिए बल्कि बैंकिंग विकास और मौजूदा क्षेत्रीय असमानताओं में उप-राष्ट्रीय भिन्नताओं वाली अन्य समान बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी निहितार्थ हैं। अंततः, अनुभाग 6 में निष्कर्ष और निहितार्थों पर चर्चा की गई है।

कार्यप्रणाली

कई अध्ययनों में वित्तीय विकास का अनुमान लगाने के लिए M3/GDP (व्यापक मुद्रा या तरल देयताएँ) या निजी ऋण/GDP जैसे संकेतकों का उपयोग किया गया है। हाल के अध्ययनों में, आर्कंड एट अल. ने मैक्रोइकॉनोमिक अस्थिरता के प्रभाव की जाँच करने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से निजी ऋण/GDP का उपयोग किया है। क्षेत्र/GDP; M3/GDP; वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंक परिसंपत्तियों के योग में वाणिज्यिक बैंक परिसंपत्तियों का हिस्सा।

हालाँकि, वित्तीय विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें विभिन्न आयाम शामिल हैं जैसे कि आउटरीच, आकार, गहराई, स्थिरता और वित्त तक पहुँच। अकेले या कुछ उपाय वित्तीय प्रणाली की जटिलता को नहीं पकड़ सकते हैं:

वित्तीय क्षेत्र का विकास एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें न केवल मौद्रिक समुच्चय और ब्याज दरें (या वापसी की दरें) शामिल हैं, बल्कि वित्तीय खुलापन, विनियमन और पर्यवेक्षण, तकनीकी प्रगति, प्रतिस्पर्धा की डिग्री और संस्थागत क्षमता जैसे कि लेनदार अधिकारों की ताकत भी शामिल है।

गहराई (बाजारों का आकार और तरलता), पहुंच (व्यक्तियों और कंपनियों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने की क्षमता) और दक्षता (संस्थाओं की कम लागत पर और स्थायी राजस्व के साथ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की क्षमता, और पूंजी बाजारों की गतिविधि का स्तर) का संयोजन।

चूंकि एकल संकेतक वित्तीय विकास की पूरी सीमा को पकड़ने में असमर्थ है, इसलिए हमने 1996-2015 के लिए 25 राज्यों के लिए समग्र बैंकिंग सूचकांक बनाया है। साहित्य का अनुसरण करते हुए, हम यूएनडीपी द्वारा अपने मानव विकास सूचकांक और अन्य यूएनडीपी सूचकांकों के निर्माण में अपनाई गई समान पद्धति का पालन करते हैं। विस्तृत पद्धति और संकेतकों का विकल्प नीचे दिया गया है।

हम प्रत्येक बैंक समूह को Dj से निरूपित करते हैं जहाँ j = 1...J है, और इसलिए, हमारे मामले में j = 3 (सार्वजनिक, निजी और विदेशी)। प्रत्येक आयाम में n संख्या में निर्धारक होते हैं जिन्हें हम Xi से निरूपित करते हैं, और i = 1 से n तक। सबसे पहले, हम प्रत्येक आयाम j के लिए Xi का मान इस प्रकार परिकलित करते हैं:

$$X_{ij}^{k} = \frac{X_{ij1}^{k} - X_{ij2}^{k}}{X_{ij3}^{k} - X_{ij1}^{k}} \quad (1)$$

यहाँ, संकेतन Xkij 1, Xkij 2 और Xij 3 क्रमशः jवें आयाम में ith निर्धारक के लिए वास्तविक (1) प्रेक्षित मान, न्यूनतम मान (2) और अधिकतम मान (3) को दर्शाते हैं। न्यूनतम और अधिकतम मान, जिन्हें 'लक्ष्य' कहा जाता है (UNDP, 2009), विभिन्न अवस्थाओं में प्रत्येक चर के न्यूनतम और अधिकतम मान हैं। अब, हम प्रत्येक आयाम Dj का मान निर्धारित करने के लिए निम्नानुसार सरल अंकगणितीय औसत का उपयोग करते हैं। हम ज्यामितीय माध्य के बजाय अंकगणितीय औसत का उपयोग मुख्य रूप से हमारे डेटाबेस में विशेष रूप से विदेशी बैंकों के लिए शून्य या शून्य के करीब अवलोकनों के मान वाले कई आयामों के कारण करते हैं। अंकगणित माध्य शून्य या बहुत कम मानों को ध्यान में रखता है जिसका अर्थ है कि उच्च मान निम्न या शून्य मानों का पूरी तरह से स्थानापन्न होते हैं।

$$D_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_{ij}^{k}}{n} \quad (2)$$

इसके बाद, हम प्रत्येक आयाम को समान भार देते हैं (आयाम j के लिए αj द्वारा दर्शाया गया है)। हम उप-राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक बैंक समूह के लिए बैंकिंग विकास सूचकांक की गणना इस प्रकार करते हैं: (3)

$$Banking\ sector\ Index = \sum_{j=1}^{J} \alpha_j D_j$$

विदेशी बैंकों के लिए जमा और ऋण दोनों पर कई मूल्य गायब हैं, खासकर पिछड़े राज्यों में। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विदेशी बैंक बहुत ही चयनात्मक हैं और विकसित और अधिक समृद्ध क्षेत्रों में स्थित होना पसंद करते हैं, तथाकथित 'क्रीम स्किमिंग' में लिप्त होते हैं और चुनिंदा बहुत ही लाभदायक फर्मों को वित्त प्रदान करते हैं। वे परिणामस्वरूप ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में फैलने से बचते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगण्य या कोई जमा/ऋण मूल्य नहीं होता है। यदि कोई डेटा उपलब्ध नहीं है तो हमने मूल्यों को शून्य पर सेट किया है। यह आदर्श नहीं है, लेकिन सीमित डेटा वाली परिस्थितियों में हमारा मानना है कि यह एक उचित समझौता है। संकेतकों का चयन कुछ अध्ययनों ने क्रॉस-कंट्री स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय विकास सूचकांक बनाए हैं। विश्व आर्थिक मंच (2012) ने सात आयामों का उपयोग किया - संस्थागत वातावरण, व्यावसायिक वातावरण, वित्तीय स्थिरता, बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ, गैर-बैंकिंग

वित्तीय सेवाएँ, वित्तीय बाज़ार, वित्तीय पहुँच और 62 देशों के लिए वित्तीय विकास सूचकांक का निर्माण किया। हांगकांग एसएआर ने 7 में से 5.3 पर उच्चतम स्कोर किया, जबकि वेनेजुएला ने सबसे कम (2.37) स्कोर किया। भारत 62 में से 40वें (3.3) स्थान पर है और पेरू, तुर्की और मैक्सिको से थोड़ा आगे तथा स्लोवाक गणराज्य और पोलैंड से पीछे है।

क्रॉस कंट्री स्तर पर, बहुआयामी वित्तीय विकास सूचकांक बनाया जिसमें आयाम शामिल हैं – बैंकिंग विकास; वित्तीय स्वतंत्रता; विनियमन और पर्यवेक्षण और संस्थागत वातावरण। संकेतकों में शामिल हैं एम2/जीडीपी, गैर-निष्पादित ऋण, ब्याज दर प्रसार, घरेलू निजी क्षेत्र का ऋण, कारोबार किए गए शेयरों का मूल्य/जीडीपी, प्रति 100,000 लोगों पर बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या, हेरिटेज फाउंडेशन से वित्तीय स्वतंत्रता, बैंक पूंजी/संपत्ति अनुपात, सूचना सूचकांक की ऋण गहराई और कानूनी अधिकार सूचकांक की ताकत। गहराई, पहुंच और दक्षता आयामों को कैप्चर करते हुए 1980 से 2013 के लिए 183 देशों के लिए वित्तीय विकास सूचकांक विकसित बैंकिंग विकास के स्तर पर पहुंचने के लिए पहुंच और बैंकिंग सेवाओं के उपयोग पर संकेतक को मिलाकर 14 प्रमुख राज्यों के लिए एक बैंकिंग सूचकांक बनाया। हमारा सूचकांक अलग है क्योंकि यह 25 राज्यों को कवर करता है, इसमें वर्षों की बढ़ी हुई संख्या शामिल है और इसके विपरीत हम सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों के लिए अलग-अलग सूचकांक बनाते हैं।

चूंकि हम बैंकों और विभिन्न बैंक समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए हम केवल बैंकिंग संकेतकों पर विचार करते हैं और तीन बैंक समूहों के लिए अलग-अलग सूचकांक बनाते हैं। विभिन्न बैंक समूहों और वर्षों के लिए उप-राष्ट्रीय स्तर पर, डेटा केवल प्रति बैंक शाखा क्रेडिट, जमा और जनसंख्या के लिए उपलब्ध है। इसलिए, अन्य अध्ययनों के बाद, हम उपरोक्त तीन चर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे पास अन्य आयामों पर बैंक समूह डेटा नहीं है, उदाहरण के लिए, वित्तीय प्रणाली की दक्षता और स्थिरता (प्रति शाखा औसत स्टाफ लागत, या राज्य स्तर पर गैर-निष्पादित संपत्ति)। इस अध्ययन में, हमने 1997 के पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट, 2001 मिलेनियम और डॉट कॉम बबल और 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट को कवर करते हुए आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से वित्तीय विकास को कुछ हद तक कैप्चर किया है। हालांकि, हमारा उद्देश्य उनमें से प्रत्येक घटना के विशिष्ट प्रभावों की पहचान या अलगाव करना नहीं है। हम तीन व्यापक संकेतकों - जमा राशि; ऋण और प्रति बैंक शाखा की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 25 राज्यों में विभिन्न बैंक समूहों के लिए समग्र सूचकांक का निर्माण करते हैं जो वित्तीय प्रणाली की गहराई और पहुंच को दर्शाता है। ऋण संकेतकों में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण; ऋण/राज्य आउटपुट और प्रति 1,000 लोगों पर ऋण खातों की संख्या शामिल हैं। जमा संकेतक जमा/राज्य आउटपुट हैं; प्रति व्यक्ति जमा खाते (प्रति 1,000 लोगों पर जमा खातों की संख्या बैंक शाखाओं तक नजदीकी पहुंच भी ऋण मांग और बैंकों द्वारा ऋण के प्रावधान में मायने रखती है। हालांकि, हालांकि उच्च बैंक ऋण/जीडीपी अनुपात वित्तीय क्षेत्र की गहराई और बेहतर वित्तीय विकास को इंगित करता है, फिर भी यह ऋण की गुणवत्ता की परवाह किए बिना केवल ऋण के आकार (मात्रा) पर केंद्रित है। बहरहाल, गहराई और आउटरीच अन्य अध्ययनों द्वारा भी अपनाए गए मानक संकेतक हैं।

हमारा डेटा 1996-2015 की अवधि को कवर करता है और बैंकिंग संकेतकों के लिए आरबीआई के वार्षिक प्रकाशनों और राज्य उत्पादन के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से प्राप्त किया गया है। प्रत्येक बैंक समूह के लिए ऋण पर उपलब्ध डेटा कुल ऋण से संबंधित है और सार्वजनिक और निजी ऋण के बीच अंतर नहीं करता है।

उद्देश्य

- क्षेत्रीय आर्थिक असमानता पर अध्ययन करने के लिए
- भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म का अध्ययन करने के लिए: राज्यों के बीच विकास अंतर का विश्लेषण

परिणाम

1996-2008 और 2009-2015 के लिए प्रत्येक राज्य के लिए सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों के लिए बैंक समूह सूचकांक महाराष्ट्र (पश्चिमी क्षेत्र) ने अन्य सभी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल (दक्षिणी क्षेत्र) का स्थान है। एक दिलचस्प अवलोकन कृषि समृद्ध राज्य पंजाब में सार्वजनिक बैंकों की उच्च उपस्थिति थी, जो विकसित और अच्छी तरह से बैंकिंग वाले राज्य महाराष्ट्र से भी अधिक थी। 1996-2008 के दौरान पंजाब में सार्वजनिक बैंक शाखाओं में तेजी से वृद्धि हुई और उसके बाद जमा और ऋण में कई गुना वृद्धि हुई। हालांकि, राज्य ने सुधार के बाद की अवधि में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और कई कारकों जैसे कि तकनीकी सफलताओं की कमी, सार्वजनिक व्यय में गिरावट, विशेष रूप से विकास व्यय, कम मानव पूंजी विकास और कृषि क्षेत्र में संकट के कारण इसकी आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई है। हालाँकि पंजाब की समग्र रैंकिंग 1996-2008 के समान ही रही, लेकिन संरचना के संदर्भ में इस अवधि के दौरान सार्वजनिक बैंकों के अनुपात में गिरावट आई, जबकि निजी बैंकों में मामूली वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, समग्र बैंकिंग सूचकांक में शीर्ष तीन और निचले तीन राज्यों की स्थिति अपरिवर्तित रही है, जो राज्यों में अभिसरण की कमी, क्षेत्रीय विकास की एकतरफाता और क्षेत्रीय असमानताओं में निरंतरता को दर्शाता है।

एक दिलचस्प खोज 2009-15 के दौरान कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय) की रैंकिंग में सुधार है, हालांकि अधिकांश अभी भी पिछड़े समूह में आते हैं। इन राज्यों में प्रति बैंक शाखा (सार्वजनिक और निजी बैंक) कवर की गई जनसंख्या में लगातार गिरावट आई है, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ाने पर सरकार के बढ़ते जोर को दर्शाता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, हमारा अध्ययन शोध प्रश्नों से शुरू हुआ: हम उप-राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय विकास को कैसे मापते हैं? राज्यों में वित्तीय विकास कितना असमान है, और क्या यह वित्तीय संस्थानों के स्वामित्व से भिन्न होता है? हमने भारतीय संदर्भ में क्षेत्रीय असमानताओं के वित्तीय आयाम को समझने की दिशा में एक कदम के रूप में उप-राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय विकास में असमानताओं की सीमा की जांच की। एक बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत विशेष रूप से जांच करने के लिए एक दिलचस्प मामला है क्योंकि यह न केवल विकास के विभिन्न चरणों में उप-राष्ट्रीय इकाइयों वाली एक बड़ी संघीय अर्थव्यवस्था है, बल्कि इसके वित्तीय क्षेत्र का स्वामित्व भी काफी विषम और विविध है। उप-राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय गहनता की सीमा की आगे जांच करने के लिए, हमारा अध्ययन वर्ष 1996 से 2015 के लिए 25 भारतीय राज्यों के लिए सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों के लिए समग्र बैंकिंग विकास सूचकांक बनाता है।

एक अन्य अध्ययन में, हमारे शोध से यह भी पता चला कि आम धारणा के विपरीत, सार्वजनिक बैंक अपनी बैंक शाखाएँ स्थापित करने में क्षेत्रीय और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि पर विचार करते हैं। अंत में, एक दिलचस्प खोज हाल के वर्षों में उत्तर-पूर्व सहित कुछ राज्यों के सूचकांक स्कोर में सुधार है जो वित्तीय समावेशन पर हाल के अभियान के कुछ शुरुआती

प्रभाव को दर्शाता है। हम दोहराते हैं कि इस अध्ययन में हमारा उद्देश्य उप-राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की जाँच करना है न कि अंतर्जातता की जाँच करना। फिर भी, भारत के भीतर अभिसरण के लिए बैंकिंग पहुँच के महत्व का परीक्षण करने के लिए कठोर विकास प्रतिगमन करने के लिए सूचकांक का उपयोग किया जा सकता है।क्षेत्रीय असमानता, समस्याकएं के कारण ही आज हम देश के सभी भागों खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने में विफल साबित हो रहे हैं. भारत को विकसित देशों के श्रेणी में लाने के लिए हमें सुदूरवर्ती गाँवों में विकास के किरणों को पहुँचाना होगा ! उपरोक्त सोध अध्ययन से ये पता चलता है कि क्षेत्रीय असमानता किसी भी देश को विकसित बनाने में सबसे बडी बाधा बनी हुई है, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, धामिक, राजनीतिक, भौगोलिक समनाता बनाये रखने के लिये इन विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया जाये ताकि भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाया जा सके।

संदर्भ

1. डॉ० विजय शंकर उपाध्याय भारत की जनजातीय संस्कृति, आदिवासी लोक कला परिषद, भोपाल, 2004
2. डॉ० विजय चौरसिया भारत की जनजातीय संस्कृति, आदिवासी लोक कला परिषद, भोपाल, 2004
3. डॉ० वेरियर एल्विनः द बैगा, आक्फोर्ड यूनिवर्सिटी, 1926
4. डॉ. सुरेश मिश्रः इतिहास के अंत से, स्वराज संस्थान, संचालनालय संस्कृति भवन, भोपाल, 2005
5. श्याम सुन्दर बादल बुन्देली का फाग साहित्य, आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल, 2000
6. "वित्तविज्ञानी सर्वेक्षण, अर्थव्यवस्था की स्थिति" वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। जुलाई 2014. अभिगमन तिथिः जुलाई 2014.
7. बेस्ले, टी. और बर्गेस, आर. (2000), 'भूमि सुधार, गरीबी में कमी और विकास: भारत से साक्ष्य', द क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 115(2): 389–430.
8. बेक, टी. और डे ला टोरे, ए. (2007), 'वित्तीय सेवाओं तक पहुँच का बुनियादी विश्लेषण', वित्तीय *बाजार, संस्थान और उपकरण, 16: 79–117.*
9. अरोड़ा, आर. (2017), 'सरकारी हस्तक्षेप और वित्तीय क्षेत्र विकास', जियानलुइगी, जी. (संपादक), विकास वित्त: पालग्रेव, पृ. 53–78.
10. डेग्रीस, एच. और ओंगेना, एस. (2005), 'दूरी, उधार संबंध और प्रतिस्पर्धा', जर्नल ऑफ फाइनेंस, 60(1): 231–266.
11. जयरत्ने, जे. और स्ट्रैहान, पी. ई. (1996), 'वित्त-विकास संबंध: बैंक शाखा विनियमन से साक्ष्य', 111(3): 639–670.
12. कौर, जे. और सिलोनी, (2011), 'सुधारों के बाद के युग में पंजाब में बैंकिंग का प्रवेश और विकास', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट; नई दिल्ली, 1(4), 23–45

13. किम, एस. (2017), 'संस्थाएँ और अमेरिकी क्षेत्रीय विकास: मैसाचुसेट्स और वर्जीनिया का एक अध्ययन', जर्नल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स (2009), 5(2): 181–205.
14. नरसिम्हम, एम. (1991), वित्तीय प्रणाली पर समिति की रिपोर्ट (रिपोर्ट)।
15. राजेश राज, एस. एन., सेन, के. और कथूरिया, वी. (2014), 4(1): 38–49।